प्रजा फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट, 2021: ‘गंभीर अपराध के 98% मामले लंबित हैं’

Hindi-khabar

2016 और 2021 के बीच छह साल की अवधि में, प्रजा फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट, ‘पुलिसिंग और कानून की स्थिति’ के अनुसार, मुंबई में औसतन द्वितीय श्रेणी के गंभीर अपराधों में केवल 2,401 परीक्षण (निर्णय/निकासी) पूरे किए गए और मुंबई में आदेश दिया गया। , 2022’, मंगलवार को जारी किया गया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस गति से, सभी लंबित मामलों पर निर्णय देने में 2021 तक और 34 साल लगेंगे।

रिपोर्ट सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के तहत प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

द्वितीय श्रेणी के गंभीर अपराधों में हत्या, हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामले शामिल हैं।

2021 तक, कुल 82,108 द्वितीय श्रेणी के गुंडागर्दी के मामले, या सभी मामलों में से 98%, मुकदमे की सुनवाई के लिए लंबित थे। केवल 1,240 मामले पूरे हुए और 485 मामले वापस लिए गए, स्थानांतरित किए गए, वापस लिए गए या रद्द किए गए। 1,240 मामलों में से, जहां परीक्षण पूरा

हो गया था, 86% बरी या बरी हो गए। हालांकि दोषसिद्धि दर केवल 14% थी, हत्या जैसे अपराधों के लिए दोषसिद्धि दर अपेक्षाकृत अच्छी थी 45%, बलात्कार 24%, छेड़छाड़ 21% और अपहरण/अपहरण 20%।

इसके अलावा, द्वितीय श्रेणी के गंभीर अपराध रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस जांच स्तर पर 25,841 और मामले लंबित हैं, जबकि पिछले वर्ष 16,713 मामले थे। इसका मतलब है कि 68% मामले विचाराधीन हैं और पेंडेंसी में 8% की वृद्धि हुई है, जबकि 2017 में यह 60% थी। कानून और व्यवस्था पुलिस के संयुक्त आयुक्त बिस्वास नांगरे पाटिल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "इस साल (2022), हमने काफी हद तक लंबित मामलों को दूर किया है।"

न्यायपालिका में बैकलॉग के अलावा, मुंबई पुलिस में रिक्तियों को लंबित पुलिस जांच के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। महाराष्ट्र पुलिस के सूत्रों के अनुसार, पिछली बार 2007 और 2012 के बीच पूरे बल के लिए स्वीकृत संख्या बढ़ाई गई थी।

"मुंबई पुलिस में रिक्ति 2018 में 22% से बढ़कर 2022 में 28% हो गई। मामलों की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के पदों का रिक्त होना भी चिंताजनक है। पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए यह 24% और सहायक पुलिस निरीक्षक के पद के लिए 13% है। जनशक्ति की कमी जांच की अवधि और गुणवत्ता को प्रभावित करती है, "प्रजा फाउंडेशन के सीईओ मिलिंद मस्के ने कहा।

Link: https://xn--i1b4b6bzau3c1bk.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%9c%e0%a4%be-%e0%a4%ab%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%82%e0%a4%a1%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%bf/